वैदेशिक-कार्य मंत्रालय

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर विचार करेगी।

वर्ष १९६१-६२ के लिये वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१६	आदिमजाति क्षेत्र	९,८७,३३,०००
१७	नागा पहाड़ियां-त्वेनसांग क्षेत्र	३,४१,५३,०००
१८	वैदेशिक-कार्य	११,२२,७७,०००
१९	पांडिचेरी राज्य	३,९५,८०,०००
२०	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय . .	२,९९,८६,०००
११३	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय . . .	८०,९६,०००

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैं वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की ओर से ये मांगें सभा के सामने रखता हूं। अभी मैं उनके बारे में कुछ शुरुआती बातें ही कहूंगा।

[अध्यक्ष महोदय पीठ सीन हुए।]

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का ताल्लुक भारत और बाहरी दुनिया के सम्बन्धों से है। इसलिये उसे संसार की कई समस्याओं से ताल्लुक रखना पड़ता है, और यह भी एक ऐसे जमाने में जब कि संसार बड़ी तेजी से बदलता जा रहा है। ऐसे हालात में इस मंत्रालय को रोजाना के प्रशासन के अलावा, नई-नई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। माननीय सदस्यों को यह ध्यान रखना चाहिये, तभी वे हमारी कठिनाइयों को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे। मैं यह नहीं कहता कि इसकी वजह से हमारी गलतियों को नजरअन्दाज कर दिया जाये, पर हां इस बात का ख्याल जरूर रखना चाहिये।

इस मंत्रालय का काम भी दिन-दिन बढ़ता जा रहा है। इसके कई कारण हैं। एक कारण यह भी है नये-नये देश आजाद होते जा रहे हैं। हमें वहां अपने प्रतिनिधि भेजने और उनके प्रतिनिधियों को अपने यहां रखने की समस्याओं पर विचार करना पड़ता है। अफ्रीका के नये आजाद देशों के बारे में यह समस्या हमारे सामने है। संसार की परिस्थिति की पेचीदगी की वजह से यह समस्या भी पेचीदा बन गई है।

आज संसार की सब से बड़ी समस्या निःशस्त्रीकरण की है। उसका सीधा असर तो हम पर इतना ज्यादा नहीं पड़ता, लेकिन समूचे संसार पर उसका जबर्दस्त असर पड़ता है, इसीलिये हम पर भी उसका असर पड़ता है। इसलिये कि अपने देश को कुछ खास कारणों से एक बड़ा अहम पार्ट अदा करना पड़ता है संसार की समस्याओं के बारे में उनको हल करने के बारे में।

इसलिये माननीय सदस्यों को वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के बारे में कुछ कहते समय, एक मोटे तौर पर उसकी नीति की चर्चा करते समय, उसकी सफलताओं और असफलताओं का लेखा-जोखा करते समय, उसके काम को ध्यान में रखना चाहिये।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हो सकता है कि मेरा ख्याल कुछ एकतरफ़ा हो। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद इस मंत्रालय की नीति एक मोटे तौर पर काफी सही रही है। पहले जो हमारी नुक्ताचीनी करते थे, अब वे भी इस बात को मानने लगे है। हम ने जब फौजी गुटों से अलग रहने की नीति दुनिया के सामने रखनी शुरू की थी, तब शायद ही कोई दूसरा देश उस तरीके से सोचता था। आज २० से भी ज्यादा बड़े देश ऐसे हैं जो फौजी गुटों में शामिल होते हुए भी हमारे देश की फौजी गुटों से अलग रहने की नीति की अहमियत समझने लगे हैं।

मिसाल के लिये लाओस को देखिये। उस देश की समस्या यही है कि लाओस सरकार पर दो मुख्तलिफ फौजी गुट अपना-अपना दबाव डालते रहे हैं। नतीजा यह है कि उसकी समस्या ज्यादा पेचीदा हो गई है। और अब सिर्फ लाओस के नेता ही नहीं, दोनों फौजी गुटों के नेता भी यह मानने लगे हैं कि लाओस का भविष्य फौजी गुटों से अलग, तटस्थ रहने में ही सुरक्षित है। और इसीलिये अब उस समस्या के हल होने के कुछ आसार दिखने लगे हैं। इसीलिये मैं ने कहा है कि अब आम तौर पर सभी देश, फौजी गुटों की नीति पर चलने वाले देश भी, हमारी नीति को पसन्द करने लगे हैं, इसकी अहमियत समझने लगे हैं। हमारे देश के लिये तो वह खास तौर पर मौजूं है।

माननीय सदस्यों को इस मंत्रालय के बारे में पहले दो-तीन बातें समझ लेनी चाहियें। पहली तो यह कि संसार तेजी से बदल रहा है, और उससे इतिहास बनता जा रहा है, ऐसा इतिहास जो आज घटित हो रहा है और बाद में लिखा जायेगा। वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का ताल्लुक उसी से है। नयी नयी ताकतें पैदा हो रही हैं, और उनकी वजह से नये नये मसले, नयी-नयी समस्यायें पैदा हो रही हैं। ऐसे हालात में कोई भी बिल्कुल ठीक ठीक नहीं कह सकता कि कल क्या होगा। कौन जानता था कि अफ्रीका की तस्वीर आज ऐसी होगी ? कोई नहीं जानता कि एटमी हथियारों का विकास हमें किस दिशा में ले जायेगा—युद्ध की तरफ या शान्ति की। इसलिये पूरे यकीन के साथ कुछ कह सकना मुश्किल है।

हर देश का भविष्य उसकी अपनी ताकत, उसकी अपनी योग्यता के साथ साथ, शेष संसार की परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। इसलिये हमारा सबसे पहला काम यही है कि हम अपनी ताकत बढ़ायें, अपने देश की अर्थ व्यवस्था मजबूत करें और लोगों के रहन-सहन की दशा और अच्छी बनायें, जिससे कि हम पूरे भरोसे के साथ अपनी समस्याओं का सामना कर सकें। काफी हद तक इसका दारोमदार हमारी पंचवर्षीय योजनाओं पर है। लेकिन एक हद तक इस बात पर भी कि हम बाहरी दुनिया के साथ अपने ताल्लुक किस तरह के बनाते है। दूसरे देशों के साथ बैरभाव होने से आगे बढ़ने में रुकावट आती है। और आज इस वक्त, हम कह सकते हैं कि संसार के अधिकतर देशों की मैत्री और सद्भावना हमारे साथ है और यह हमारा सौभाग्य है संसार के दो सबसे बड़े देश—अमरीका और सोवियत यूनियन की मैत्री और सद्भावना हमारे साथ है। खास तौर से तब, जबकि इन दोनों के ताल्लुकात कोई खास दोस्ताना नहीं रहे हैं। वे अपने अपने फौजी-गुटों के नेता हैं।

इसलिये उन दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखना अपने आप में एक बड़ी सफलता है। उन दोनों देशों के हर काम की ताईद किये बिना, उनके साथ मैत्री बनायें रखना एक बड़ी बात है। इसीलिये कि वे दोनों हमारी नीति की अहमियत महसूस करते हैं। वे हमारी नीति मानें या न मानें, लेकिन उस पर पूरी तरह गौर जरूर करत हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह बात सिर्फ दो देशों---चीन और पाकिस्तान---पर पूरी-पूरी लागू नहीं होती । बाकी सभी देशों पर लागू होती है । लेकिन पाकिस्तान की जनता के साथ भी हमारी उतनी कटुता नहीं रही । उसमें काफी कमी ही गई है । हां, सरकारी स्तर पर कुछ समस्यायों को लेकर जब-तब टकराव पैदा हो जाता है ।

चीन और हमारे देश के बीच खाई चौड़ी हो गई है । हम सभी को चीन का रवैया बहुत बुरा लगा है । इस पर भी हमारी कोशिश यही रही है कि कोई ऐसा कदम न उठाया जाय जिससे कि बात हाथ से निकल जाय । हमें मौजूदा हालात के साथ आगे आने वाले वक्त का भी ख्याल रखना पड़ता है और भारत और चीन जैसे इतने बड़े बड़े दो पड़ौसी देशों के आपसी ताल्लुकात तो इन दोनों ही नहीं समूचे संसार के लिये बड़ी अहमियत रखते हैं ।

इसलिये हमने अपनी बेहद नाराजगी को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया है । हमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिससे कि और ज्यादा पेचीदगी पैदा हो जाय । हमारा नजरिया यही रहा है कि यदि कोई मुसीबत आ ही जाय, तो हम उसका सामना करने के लिये अपने को तैयार करते चलें ।

कुछ माननीय सदस्यों ने शिकायत की है कि हमने ज्यादा कड़ी कार्यवाही क्यों नहीं की । उनको मेरा यही जवाब है कि कड़ी कार्यवाही तभी की जाती है जब और कोई चारा न रहे । कड़ी कार्यवाही की बात भी तभी की जानी चाहिये जब वह की जा सकती हो । समझदारी इसी में है ।

इस के बारे में हमने दूसरी तरह की कार्यवाही की है । और जो भी किया है वह इसी नजरिये से कि संसार के सामने हमारी बात की, हमारे रुख की पुख्तगी साबित हो---संसार के सभी लोग समझ लें कि हमारी बात सही है । इसी नजरिये से यह मामला उन अधिकारियों को सौंपा गया था, जिन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है । उस रिपोर्ट को सदस्यों में बांटा जा चुका है । हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं होने दी है । जिससे हमारी स्थिति कमजोर हो जाय । स्थिति को ज्यों की त्यों बनाये रखना, एक जगह जम कर खड़े होना, खुद एक मजबूती की बात है । बिना ताकत और मजबूती के एक जगह जम कर खड़ा नहीं रहा जा सकता । और एक जगह अपना पैर जमा देने का और उसे जमाये रखने का भी असर होता है, नतीजा निकलता है । कमजोर आदमी तो जमकर खड़ा नहीं रह सकता । यह सोचना गलत है कि सिर्फ जंग के जरिये ही समस्याएं हल की जा सकती हैं । और यह भी बिल्कुल नामुमकिन नहीं कि शायद किसी दिन चीन सरकार भी हमारी बात की सही समझने लगे । इसीलिये हमारी सारी कोशिश यही रही है कि चीन सरकार महसूस कर ले कि उसने गलती की है और उसे अपनी फौजें हटा लेनी चाहियें ।

हमारे अधिकारियों ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उसे माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा और उनकी मेहनत और लगन की दाद दी होगी, खास तौर से रिपोर्ट के उस भाग की जिसमें पूरा इतिहास पेश किया गया है ।

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : दाद तो बहुत पहले भी दी जा सकती थी ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सभी लोग माननीय सदस्य जितने काबिल नहीं हैं । इतिहास के जानकार लोगों ने भी उस रिपोर्ट के लिये उन अधिकारियों की तारीफ की है । उन्होंने रिपोर्ट में इतिहास को पेश करने के तरीके की तारीफ की है । और इस बात की भी कि उसमें इतना ज्यादा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

वक्त नहीं लगा मैं इस पर कोई बहस खड़ी नहीं करना चाहता। इस काम के लिये बहुत अनुसन्धान अपेक्षित था। निस्सन्देह इसे पहले होना चाहिये था पर हमने जो कुछ किया है वह भी वर्षों के परिश्रम के बाद ही किया है। अतः पहले भी काम होता रहा है पर रफ्तार बाद ही में तेज हुई है। किन्तु जब से हमारा ऐतिहासिक विभाग बना है तभी से टिप्पण तैयार किये जा रहे थे और बहुत कुछ काम किया गया था। किन्तु इस घटना के बाद तेजी से काम शुरू किया गया।

मैं सभा से यही कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर बड़ी व्यापक दृष्टि से ध्यान दिया जाय क्योंकि यह संसार सदा युद्ध के निकट आ रहा है और उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अतः इसी संदर्भ में इन चीजों पर विचार करना चाहिये---पाकिस्तान की समस्या यद्यपि कुछ हद तक भिन्न प्रकार की है तथापि बनी तो रही है। इसी प्रकार हमारा कांगो, लाओस आदि में दखल भी नयी चीज नहीं--सब पुरानी बातें हैं। इस दुनिया में हर समय नयी बातें पैदा होती हैं।

बड़ी ताकतें, अमेरिका और रूस भी सदा यही सोचा करते हैं कि वह एक मामले में क्या कार्यवाही करें। बड़ी से बड़ी ताकत भी आज अपनी बात नहीं मनवा सकती उन्हें भी हालात के अनुसार चलना पड़ता है। और यदि किसी दिन हमारी यह स्थिति हो कि हमारे देश की बात सभी मानें या हमारा आदेश चले तो यह संसार के लिये दुर्दिन होगा।

अब कुछ लोग यह महसूस करने लगे हैं कि हम अपनी नीति को बदलने लगे हैं। यदि वे सूक्ष्म दृष्टि से सारी स्थिति का अवलोकन करें तो पता चलेगा कि परिवर्तन केवल हमारी नीति में ही नहीं—थोड़ा थोड़ा हर देश में हो रहा है। किन्तु हमारी बुनियादी नीति में ज्यादा परिवर्तन नहीं हैं। अन्य देशों की नीतियों में ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो हमें उनके निकट ले आए हैं।

आप अमेरिका की नीति ही को देखें। नये प्रशासन के बाद से वहां की नीतियों में काफी परिवर्तन हुआ है और उसके कारण हम और भी निकट हो गये हैं।

यदि भलाई होती हो तो नीति बदलने में खराबी नहीं। किन्तु अन्य देश हमारी नीति को ठीक समझने लगे हैं।

इस समय इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता कि वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में हम इस बदलती दुनिया की गतिशीलता का अनुसरण ठीक तरह से कर रहे हैं। भविष्य का दिग्दर्शन कराने के लिये हमें भूत से अधिक सहायता नहीं मिलती। मन्त्रालय के जिम्मे कितने ही नये काम हैं। अनेक काम ऐसे हैं जिनका वैसे उससे कोई सम्बन्ध नहीं पर हम उनका काम भी करते रहेंगे। मेरा अनुमान है कि यह सभा इन्हीं व्यापक नीतियों का समर्थन करेगी जिनसे हमें काफी सफलता भी प्राप्त हुई है।

सब बातें हमारी इच्छानुसार नहीं हो सकतीं और इसी कारण खेद करने से भी कुछ नहीं बन सकता। यह बात किसी उन्नत राष्ट्र को शोभा नहीं देती। यह अपरिपक्वता की बात है। इसका यह अर्थ नहीं कि हम गलतियां नहीं करते। पर हमें खुशी होगी जो हमारी गलतियां हमें बताई जायेंगी।

अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि इन मांगों का समर्थन किया जाय।